



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2005/वैशाख 20, 1927

No. 75]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2005/VAISAKHA 20, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मई, 2005

सं. टीएएमपी/11/2005-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, अपने वर्तमान दरमान की वैधता बढ़वाने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश 5 अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/11/2005-एनएमपीटी

आदेश

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)

आवेदक

(अप्रैल 2005 के 25 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन को अनुमोदन प्रदान करते हुए 9 अगस्त 2001 को एक आदेश पारित किया था। संशोधित दरमान के साथ वह आदेश भारत का राजपत्र संख्या 250 के माध्यम से 19 सितम्बर 2001 को अधिसूचित किया गया था।

2. कथित आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 दो वर्ष की लागत विवरणी द्वारा प्रतिबिम्बित लागत स्थिति पर आधारित था। दो वर्ष का निर्धारित प्रशुल्क वैधता चक्र का अनुपालन करते हुए, एनएमपीटी का वर्तमान दरमान अगस्त 2003 में संशोधन के लिए अपेक्षित हो गया।

3.1. एनएमपीटी ने अपने दरमान की वैधता अवधि बीतने के एक वर्ष बाद अपने दरमान की वैधता 31 अगस्त 2005 तक बढ़वाने का प्रस्ताव किया है। एनएमपीटी ने हमारे अनुरोध पर तत्पश्चात् प्रमुख गतिविधियों के लिए समुचित लागत विवरणी समेकित लागत विवरणी और मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) को छोड़कर समूचे पत्तन की लागत विवरणी दाखिल की।

3.2. एनएमपीटी ने बताया है कि लागत विवरणियों में इस प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पारित आदेश की दृष्टि से तटीय पोतों / तटीय कार्गो / कन्टेनरों को प्रदत्त 60% रियायत के कारण प्रचालनीय आय में कमी पर विचार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार गहरी जलराशि वाले बर्थों के निर्माण, पूंजीगत निकर्षण, रेलवे सुविधाएँ और सड़कें जैसी परियोजनाओं पर होने वाले पूंजीगत व्यय, जो वर्ष 2004-05 और 2005-06 में पूंजी में परिवर्तित हो सकता है, पर भी लागत विवरणी में विचार नहीं किया गया है।

(1)

3.3. एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई लागत विवरणी में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए प्रचालनीय आय में 6.79% के औसतन घाटे को प्रतिबिम्बित किया गया है। इसने बताया है कि पत्तन ने संशोधित मार्गदर्शियों के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेशित पूंजी पर आमदनी (आरओसीई) प्राप्त नहीं किया है। इसके बावजूद, इसने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह इसके प्रचलित दरमान को अगस्त 2003 में इसकी वैधता समाप्त होने के समय से दो वर्ष तक अर्थात् अगस्त 2005 तक लागू रखने की अनुमति दे दे। इसने अपने प्रचलित दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव समय से बहुत पहले प्रस्तुत करने पर अपनी सहमति दे दी है।

4.1. लागत विवरणियों की प्राथमिक जाँच पड़ताल के आधार पर एनएमपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्युत्तर में, एनएमपीटी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है और उसने संशोधित लागत विवरणी भी दाखिल कर दी है।

4.2. संशोधित लागत विवरणी वर्ष 2005-06 में समूचे पत्तन के लिए 7.57% की घाटे की स्थिति दर्शाती है और एमआरपीएल तथा केआईओसीएल गतिविधियों को छोड़कर पत्तन के लिए 11.3% के घाटे को दर्शाती है। एनएमपीटी ने इस प्रकार अपने दरमान की वैधता के विस्तार के लिए आग्रह किया है।

5.1. यह देखा गया है कि वीआरएस भुगतान और पिछली देयताओं को पूरा करने के लिए पेशन निधि की मद में योगदान वर्ष 2005-06 के प्रेक्षणों में सम्मिलित किए गए हैं। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों में विशेष रूप से निदेश दिया गया है कि प्रशुल्क निर्धारण करते समय वेतनादि / पेशन बकाया, वीआरएस क्षतिपूर्ति, पिछली देयताओं के लिए पेशन निधि में योगदान को ग्राह्य लागत के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा। पत्तन को अपनी यह देयता विशेष रूप से अलग रखे गये कोश / प्रावधान को छोड़कर संचयित अधिशेष / निधियों से पूरी करनी चाहिए और इस मात्रा में ये इस प्रकार पूरी न की जा सके, उस मात्रा के लिए एक उपयुक्त विशेष दर एक सीमित अवधि के लिए, ऐसी देयताओं को पूरा करने हेतु निर्धारित की जा सकती है। इस प्राधिकरण द्वारा यह कार्यविधि इससे भी पहले वेतन और पेशन के बकाया की वसूली के लिए कोलकाता पत्तन न्यास में और सुपरवाइजरी कर्मचारियों आदि से संबंधित वेतन बकाया की देयता पूरी करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास में भी अपनाई जा चुकी है। तृतीकोरिन पत्तन न्यास में, पूंजीगत निकर्षण के लिए प्राप्त किए गए विदेशी मुद्रा ऋण को सेवा प्रदान करने के लिए एक विशेष दर सुनिश्चित की गई थी।

5.2. जैसाकि एमआरपीएल और केआईओसीएल दो समर्पित जेट्टियाँ हैं जो विशेष रूप से इन दो उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए ही निर्माण की गई हैं और अलग-अलग समझौता ज्ञापन से शासित होती हैं। जहाँ तक इन दो उपयोगकर्ताओं से प्रशुल्क इकट्ठा करने की बात है, इन दो अलग-अलग गतिविधियों में घाटे के लिए, अन्य उपयोगकर्ताओं पर बोझ लादना उपयुक्त नहीं पाया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि एनएमपीटी, अलग-अलग समझौता ज्ञापनों में स्वीकृत विशिष्ट कार्यविधि के कारण इन दो गतिविधियों में अधिकतम अनुमेय आरओसीई प्राप्त नहीं कर पाता है तो पत्तन, समूचे पत्तन के लिए पूर्ण आरओसीई का दावा करके इन दो गतिविधियों की (सहायता / सहाय) नहीं ले सकता। अतएव, समूचे पत्तन के लिए अधिकतम अनुमेय आरओसीई, अलग-अलग प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत अनुमेय आरओसीई के कुल योग तक सीमित किया जाना चाहिए। एनएमपीटी को परामर्श दिया जाता है वह व्यापक समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करते समय इस प्रेक्षण का ध्यान रखे।

5.3. वर्ष 2005-06 में निवेशित पूंजी प्रेक्षण में, इस वर्ष पूरा होने के संभावित बहुउद्देशीय गहरे ड्राफ्ट की मद में पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित पाया गया है। तथापि, ऐसा करते समय, इस बर्थ के चालू हो जाने पर अतिरिक्त यातायात को, वर्ष 2005-06 के यातायात प्रेक्षणों में सम्मिलित किया हुआ नहीं पाया गया है।

6.1. एनएमपीटी ने, एक वर्ष से भी अधिक समय निकल जाने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् अगस्त 2003 से अगस्त 2005 तक दरों के विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वास्तव में, इसे इस प्राधिकरण के पास, अपने दरमान की वैधता अगस्त 2003 में समाप्त होने से बहुत पहले आना चाहिए था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि किसी भी उपयोगकर्ता ने एनएमपीटी के वर्तमान दरमान के प्रति कोई भी बिन्दुवार / तार्किक आपत्ति व्यक्त नहीं की है। एनएमपीटी द्वारा मांगा गया यह विस्तार अब से अगस्त 2005 तक केवल चार माह ही प्रभावी रहेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रशुल्क निर्धारण के लिए हाल ही में घोषित संशोधित मार्गदर्शियों को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण, इससे पहले अनुमोदित दरों की वैधता को सितम्बर 2005 तक विस्तार प्रदान करता है।

6.2. एनएमपीटी को परामर्श दिया जाता है कि वह मुख्य गतिविधियों / उप-गतिविधियों की निर्धारित प्रोफार्मा में आनुषंगिक लागत विवरणी के साथ, तीन वर्षों के लिए प्रेक्षण देते हुए, संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुरूप अपने दरमान के संशोधन हेतु 30.06.2005 तक व्यापक प्रस्ताव दाखिल कर दे ताकि यह प्राधिकरण सितम्बर 2005 तक इसके दरमान की समीक्षा / संशोधन कर सके।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर बताए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अपने पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/18/2001-एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर परिवर्तित वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितम्बर 2005 तक बढ़ाता है। एनएमपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अगली समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिकतम 30 जून 2005 तक अवश्य प्रस्तुत कर दे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th May, 2005

No. TAMP/11/2005-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal received from the New Mangalore Port Trust for extension of the validity of its existing Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No : TAMP/11/2005-NMPT

ORDER

(Passed on this 25th day of April 2005)

This Authority had passed an Order on 9 August 2001 approving the general revision of Scale of Rates (SOR) of the New Mangalore Port Trust (NMPT). The Order along with the revised SOR was notified in the Gazette of India on 19 September 2001 vide Gazette No. 250.

2. The SOR approved by this Authority in the said Order was based on the cost position reflected by the cost statement for the two years i.e. 2001-02 and 2002-03. Following the two year tariff validity cycle prescribed then, the existing SOR of the NMPT fell due for revision in August 2003.

3.1. The NMPT after expiry of almost one year of the validity of its SOR has proposed for extension of its SOR till 31 August 2005. The NMPT on our request has subsequently filed the relevant cost statements for the principal activities, consolidated cost statement and cost statement for the port as a whole excluding Mangalore Refinery Petrochemicals Limited (MRPL) and the Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL).

3.2. The NMPT has stated that the cost statements do not take into consideration reduction in the operating income on account of 60% concession offered to coastal vessels/ coastal cargo / containers in view of the recent order passed by this Authority. Like-wise the capital expenditure on projects like creation of deep draught berth, capital dredging, railway facilities and roads, likely to be capitalised during the years 2004-05 and 2005-06 have also not been considered in the cost statement.

3.3. The cost statement furnished by the NMPT reflects an average deficit of 6.79% of the operating income for the years 2004-05 and 2005-06. It has stated that the port has not achieved the Return on Capital Employed (ROCE) prescribed by this Authority as per the revised guidelines. Nevertheless, it has requested this Authority to permit levy of prevailing SOR for two years from the expiry of its validity in August 2003 till August 2005. It has agreed to submit its proposal for revision of its SOR well before time.

4.1. Based on a preliminary scrutiny of the cost statements, the NMPT was requested to furnish additional information / clarification on various points. In response, the NMPT has furnished the requisite information and has also filed revised cost statement.

4.2. The revised cost statement indicates a deficit position of 7.57% for the port as a whole for the year 2005-06 and a deficit of 11.3% for the port excluding MRPL and KIOCL activities. The NMPT has thus reiterated its request for extension of its SOR.

5.1. It is observed that VRS payments and contribution towards pension fund to meet the past liability is included in its projections for the year 2005-06. The revised tariff guidelines specifically prescribes that the arrears of wages/ pension, VRS compensation, contribution of Pension Fund for past liability, etc., will not be allowed as admissible cost while determining the tariff. The port has to meet this liability from the accumulated surpluses/ reserves other than specifically earmarked funds or provisions and to the extent it cannot be so met, a suitable special rate for a limited period may be prescribed to meet such liabilities. This approach has been adopted by this Authority even earlier at Kolkata Port Trust for recovery of arrears of salary and pension and at Mumbai Port Trust to meet the liability of wage arrears relating to supervisory staff, etc. Even at the Tuticorin Port Trust a special rate was prescribed for servicing the foreign currency loan availed for capital dredging.

5.2. Since the MRPL and the KIOCL are the two dedicated jetties created specifically for these two users and are governed by separate Memorandum of Understanding (MOU) as regards collection of tariff from these two users, it is not found appropriate to burden the other users for deficit in these two respective activities. In other words, if NMPT does not achieve the maximum permissible ROCE in these two activities because of the specific methodology agreed in the respective MOUs, the port cannot seek the other activities to top up the ROCE deficit of these two activities by claiming full ROCE for the port as a whole. The maximum permissible ROCE for the port as whole should, therefore, be restricted to the aggregate of permissible ROCE under individual major activities. The NMPT is advised to take the note of this observation while formulating its proposal for comprehensive review.

5.3. The capital employed projections for the year 2005-06 is found to include the capital expenditure towards deep draft multipurpose berth anticipated to be completed in this year. While doing so, the additional traffic on account of commissioning of this berth is, however, not found to have been considered in the traffic projections for the year 2005-06.

6.1. The NMPT has filed this proposal for extension of rates for period of two years i.e. August 2003 to August 2005 after lapse of more than a year. It should, in fact, have approached this Authority with its proposal well before the expiry of the validity of its SOR in August 2003. It is relevant to mention that none of the users have raised any pointed objection to the existing Scale of Rates of the NMPT. The extension sought by the NMPT is effectively only for four months from now till August 2005. In view of this position, and also recognising time required to formulate a general revision proposal by the port keeping in view the recently announced revised guidelines for tariff fixation, this Authority extends the validity of the rates approved earlier till September 2005.

6.2. The NMPT is advised to file its comprehensive proposal for revision of its Scale of Rates along with the relevant cost statement for the main activities/ sub-activities in the prescribed proforma giving projections for three years in line with the revised tariff guidelines by 30 June 2005 to enable this Authority to review / revise its SOR by September 2005.

7. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Scale of Rates approved vide its earlier Order number TAMP/18/2001 dated 9 August 2001, as amended from time to time, till 30 September 2005. The NMPT is directed to file its comprehensive proposal for next review by 30 June 2005 latest.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/05-Exty.]